# *निजी कॉरपोरेट निवेश: 2023-24 में संवृद्धि और 2024-25 के लिए संभावना*

*कमल गुप्ता, राजेश बी कावेड़िया, सुक्ति खांडेकर और स्निग्धा योगिन्द्रन द्वारा ^*

*यह लेख 2023-24 के दौरान बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के आधार पर निजी कॉरपोरेट्स के निवेशगत इरादों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की कुल परिकल्पित लागत 2023-24 के दौरान ₹3.91 लाख करोड़ के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई, जिसमें से 54 प्रतिशत को वर्ष के अंत तक निवेश करने की योजना है। पाइपलाइन परियोजनाओं के वित्तपोषण की चरणबद्ध रूपरेखा से पता चलता है कि परिकल्पित पूंजीगत व्यय 2023-24 में ₹1.59 लाख करोड़ से 2024-25 में उल्लेखनीय रूप से बढ़कर ₹2.45 लाख करोड़ हो जाएगा। बढ़ती घरेलू मांग और क्षमता उपयोग, कॉरपोरेट्स की बेहतर लाभप्रदता, निरंतर ऋण मांग, व्यापार आशावाद और बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का जोर, साथ ही निवेश गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत उपाय, निजी पूंजी निवेश के लिए अच्छे संकेत हैं।*

## परिचय

भारत के दीर्घकालिक विकास के प्रमुख चालक, निजी कॉरपोरेट्स द्वारा पूंजी निवेश, कोविड-19 महामारी के दौरान कम होने के बाद, गति पकड़ रहा है। बैंकों और निजी कंपनियों का मजबूत तुलन पत्र, बेहतर कॉरपोरेट लाभ, बढ़ती क्षमता उपयोग, निरंतर ऋण मांग, व्यावसायिक भावनाओं में आशावाद और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर सरकार का जोर[1] निजी पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) चक्र के लिए अच्छा संकेत है, जो निवेश के माहौल और अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को दर्शाता है और आर्थिक प्रगति को सुगम बनाता है।

चूंकि कॉरपोरेट के तुलन पत्र को अंतिम रूप देने में समय लगता है, इसलिए कई देश कॉरपोरेट निवेश और संभावित योजना पर निकट अवधि की संभावनाओं का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण-आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं। ऐसे सर्वेक्षण फर्मों के निवेश इरादों के प्रत्यक्ष आकलन के लिए निवेश की मात्रा और समय के बारे में प्रमुख जानकारी प्रदान करते हैं, जो निकट से मध्यम अवधि में साकार होने की उम्मीद है।

भारतीय संदर्भ में, रिज़र्व बैंक निवेश परिदृश्य का आकलन करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों ( एफआई )[2] द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की निगरानी के माध्यम से निजी पूंजीगत व्यय योजनाओं पर नज़र रख रहा है।[3] यह लेख 2023-24 के दौरान बैंक/एफआई द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के आधार पर निजी कॉरपोरेट्स के निवेशगत इरादों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसे पूंजीगत व्यय वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों द्वारा समर्थित बनाया गया है, जहां परियोजनाओं की कुल लागत को बैंकों/एफआई द्वारा वित्तपोषित हिस्से तक सीमित करने के बजाय एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए माना जाता है।

लेख को पाँच खंडों में संरचित किया गया है। खंड II अध्ययन में इस्तेमाल की गई कार्यप्रणाली और मान्यताओं को निर्धारित करता है। समीक्षा अवधि (यानी, 2023-24) के दौरान स्वीकृत या अनुबंधित परियोजनाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं, उनके वित्तपोषण और क्षेत्रों और उद्योगों के संदर्भ में वितरण संबंधी पहलुओं को खंड III में प्रस्तुत किया गया है । खंड IV स्वीकृत/अनुबंधित ऋणों/वित्तपोषण की चरणबद्ध रूपरेखा से संबंधित है और कॉरपोरेट निवेश की वृद्धि का अनुमान लगाता है, जबकि खंड V में अध्ययन का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

## II. कार्यप्रणाली और मान्यताएँ

निजी कॉरपोरेट्स की निवेश गतिविधि के निकट-अवधि के दृष्टिकोण के आकलन के लिए, रंगराजन (1970) द्वारा प्रस्तावित पद्धतिगत ढांचे को अपनाया गया है। इस उद्देश्य के लिए, निवेश के

---

^ लेखक सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग से हैं। लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

1 आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट (2023-24) और आरबीआई द्वारा किए गए विभिन्न मौद्रिक नीति संबंधी अग्रिम सर्वेक्षण।

2 इसमें सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, प्रमुख निजी क्षेत्र और विदेशी बैंक, तथा वित्तीय संस्थान शामिल हैं जो परियोजना वित्तपोषण में सक्रिय रूप से शामिल हैं, अर्थात भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई), जीवन बीमा निगम (एलआईसी), विद्युत वित्त निगम (पीएफसी), भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) और भारतीय निर्यात-आयात बैंक (ईएक्सआईएम)।

3 निजी कंपनियों के निवेश परिदृश्य का विश्लेषण नियमित रूप से लेखों के रूप में जारी किया जाता है, शुरू में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में तथा 1989 से आरबीआई बुलेटिन में।

इरादों पर डेटा तीन अलग-अलग स्रोतों से इकट्ठा किया जाता है, अर्थात, (i) बैंक और एफआई जो निजी कॉरपोरेट्स को प्रोजेक्ट फाइनेंस के कारोबार में शामिल हैं, (ii) बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) [विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (एफसीसीबी) जारी करने सहित), रुपया मूल्यवर्गित बॉन्ड (आरडीबी)] के माध्यम से पूंजीगत व्यय के उद्देश्य से जुटाए गए वित्त, और (iii) पूंजीगत व्यय के उद्देश्य से निजी कॉरपोरेट्स द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ), अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) और अधिकार प्रस्ताव के माध्यम से जुटाई गई निधियाँ।

यह अध्ययन विशेष रूप से उन परियोजनाओं पर केंद्रित है जिन्हें उपर्युक्त स्रोतों से धन प्राप्त होता है, जिनकी परियोजना लागत ₹10 करोड़ से अधिक है, तथा परियोजना में अधिकांश स्वामित्व निजी कंपनियों के पास है। केंद्र और/या राज्य सरकारों के पास अधिकांश हिस्सेदारी वाली परियोजनाएं, तथा ट्रस्टों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं इस अध्ययन के दायरे से बाहर हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक परियोजना को डेटासेट में केवल एक बार शामिल किया जाए, ताकि दोहरी गणना और उसके परिणामस्वरूप अधिक अनुमान लगाने से बचा जा सके।

ये अनुमान इस धारणा के तहत निकाले गए हैं कि कंपनियाँ अपनी पूर्वानुमानित पूंजीगत व्यय योजनाओं का पालन करती हैं। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये अनुमान राष्ट्रीय खातों में दिए गए वास्तविक निजी कॉरपोरेट निश्चित निवेश डेटा से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि (ए) कुछ परियोजना निवेश इरादों में उनकी नियोजित राशि और समय के संदर्भ में संशोधन हो सकते हैं; (बी) कुछ परियोजनाओं के वित्तपोषण स्रोत आंतरिक संसाधनों और/या अन्य स्रोतों, जैसे कि पूंजी बाजार/बांड वित्तपोषण और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) से जुटाई गई निधियाँ में स्थानांतरित हो सकते हैं; और (सी) कुछ नई परियोजनाएँ आ सकती हैं और कुछ नियोजित परियोजनाएँ स्थगित हो सकती हैं।

## III. स्वीकृत/अनुबंधित परियोजनाओं की विशेषताएं

2023-24 के दौरान निजी कॉरपोरेट्स के निवेश के इरादे उत्साहपूर्ण रहे, जैसा कि परियोजनाओं की बढ़ती कुल संख्या के साथ-साथ बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में भी परिलक्षित होता है। 2023-24 के दौरान, लगभग 944 परियोजनाओं को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सहायता मिली, जिनकी परियोजनाओं की कुल लागत ₹3,90,978 करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष 547 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिनकी कुल लागत ₹2,66,546 करोड़ थी (अनुलग्नक सारणी ए1)।

2023-24 के दौरान, पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से कोई वित्तपोषण नहीं लेने वाली 438 निजी कंपनियों ने पूंजीगत व्यय के उद्देश्य से ईसीबी के माध्यम से ₹1,68,396 करोड़ जुटाए, जबकि 123 अन्य कंपनियों ने अपनी पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) मार्ग के तहत घरेलू इक्विटी निर्गमों के माध्यम से ₹6,310 करोड़ जुटाए। कुल मिलाकर, 2023-24 के दौरान 1,505 परियोजनाओं की निवेश योजनाएँ बनाई गईं, जिनमें ₹5,65,684 करोड़ के रिकॉर्ड निवेश इरादे थे, जबकि 2022-23 में 982 परियोजनाओं में ₹3,51,276 करोड़ के निवेश इरादे थे (अनुलग्नक सारणी ए1-ए4)।

### i) आकार के अनुसार

परियोजनाओं के आकार-वार वितरण ने विभिन्न आकारों में परियोजनाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई। 2023-24 के दौरान, ग्यारह मेगा प्रोजेक्ट (परियोजना लागत ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक) और 77 बड़ी परियोजनाएं (₹1000 करोड़-₹5000 करोड़) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत की गईं, जिनकी हिस्सेदारी क्रमशः कुल परियोजना लागत का 21.7 प्रतिशत और 37.1 प्रतिशत थी। इन मेगा/बड़ी परियोजनाओं की चरणबद्ध योजनाओं से कोई भी विचलन मध्यम अवधि में समग्र पूंजीगत व्यय पैटर्न को प्रभावित कर सकता है (अनुलग्नक सारणी ए5)।

### ii) उद्देश्यानुसार

हाल के रुझानों के अनुरूप, 2023-24 के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की कुल लागत में हरित क्षेत्र (नई) परियोजनाओं में निवेश का हिस्सा लगभग 89 प्रतिशत रहा, जो भविष्य में निजी कॉरपोरेट्स द्वारा संभावित क्षमता विस्तार की ओर इशारा करता है। मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण में निवेश का हिस्सा कुल परियोजना लागत में 8.6 प्रतिशत रहा (अनुलग्नक सारणी ए6)।

### iii) उद्योगवार

उद्योगवार वितरण दर्शाता है कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र [4] प्रमुख क्षेत्र बना रहा, जिसकी परियोजनाओं की कुल लागत में 55.5

[4] बुनियादी ढांचा क्षेत्र में (क) बिजली, (ख) दूरसंचार, (ग) बंदरगाह और हवाई अड्डे, (घ) भंडारण और जल प्रबंधन, (ङ) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), औद्योगिक, जैव प्रौद्योगिकी और आईटी पार्क, और (च) सड़क और पुल शामिल हैं।

**चार्ट 1: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में प्रमुख उद्योगों की हिस्सेदारी**

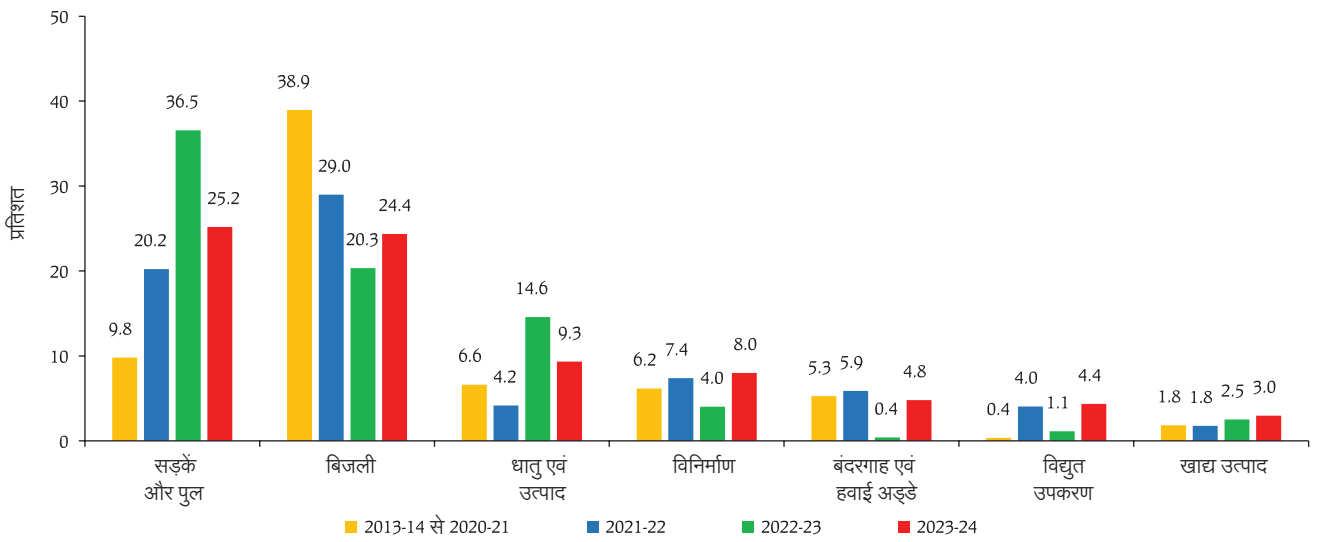


**स्रोत:** बैंकों/पीआई से एकत्रित परियोजना वित्त संबंधी आंकड़े और लेखकों की गणना।

प्रतिशत हिस्सेदारी रही, जो मुख्य रूप से 'सड़क और पुल' और 'बिजली' (अनुलग्नक सारणी ए7) में निवेश द्वारा संचालित है। बुनियादी ढांचे के अलावा, अन्य प्रमुख उद्योगों में, धातु और धातु उत्पाद, निर्माण, विद्युत उपकरण और खाद्य उत्पादों ने भी परियोजनाओं की कुल लागत में एक बड़ा हिस्सा लिया (चार्ट 1 और अनुलग्नक सारणी 7)।

### iv) राज्यवार

स्वीकृत परियोजनाओं के राज्यवार वितरण से पता चला है कि शीर्ष पांच राज्य अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने मिलकर 2023-24 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत का लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा वहन किया (चार्ट 2 और अनुलग्नक सारणी ए8)[5]।

**चार्ट 2: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में प्रमुख राज्यों की हिस्सेदारी**

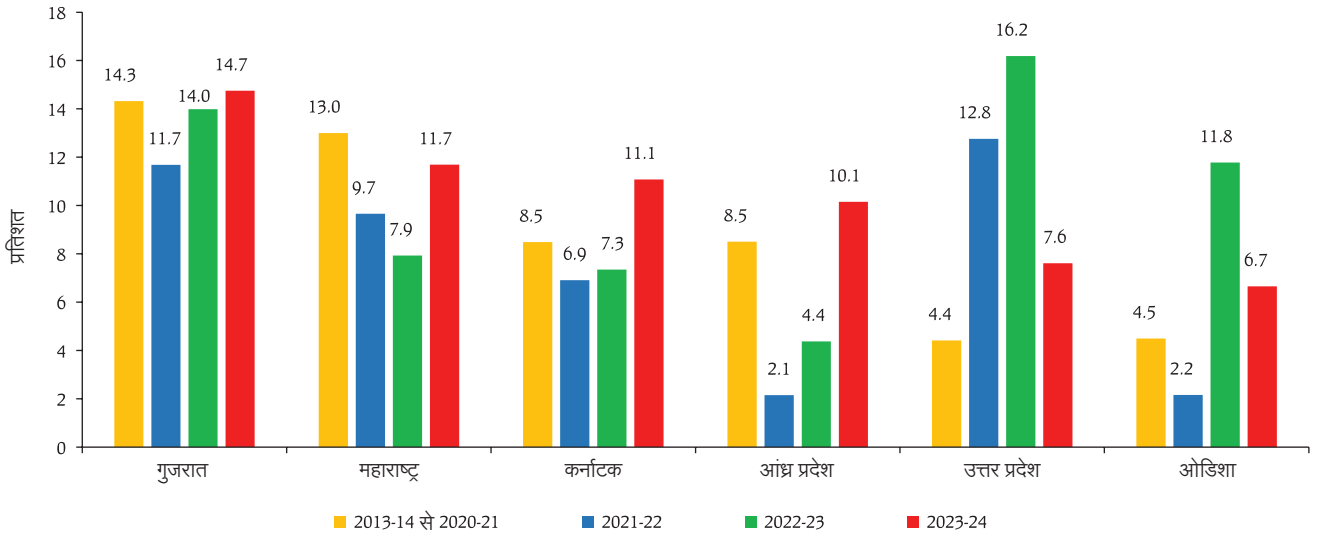


**स्रोत:** बैंकों/पीआई से एकत्रित परियोजना वित्त संबंधी आंकड़े और लेखकों की गणना।

[5] कई राज्यों में फैली परियोजनाओं को "बहु-राज्य" परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

## IV. निवेश इरादों की चरणबद्ध रूपरेखा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध रूपरेखा निजी कॉरपोरेट्स के निकट-अवधि (एक वर्ष आगे) निवेश दृष्टिकोण प्रदान करती है। 2023-24 में परियोजनाओं के समूह से चरणबद्धता यह दर्शाती है कि कुल प्रस्तावित पूंजीगत व्यय का लगभग 54 प्रतिशत (₹2,12,266 करोड़) वर्ष के अंत तक निवेश करने की योजना बनाई गई थी, जबकि 29.7 प्रतिशत (₹1,15,928 करोड़) 2024-25 में और अन्य 16.1 प्रतिशत (₹62,783 करोड़) बाद की अवधि में खर्च करने की योजना है। 2023-24 तक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की चरणबद्ध रूपरेखा के आधार पर, 2023-24 के दौरान परिकल्पित पूंजीगत व्यय में 41.7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो 2,80,975 करोड़ रुपये हो गई (अनुबंध सारणी ए1)।

निजी कॉरपोरेट्स द्वारा ईसीबी और आईपीओ रूट के माध्यम से जुटाए गए संसाधन उनकी निवेश गतिविधियों के वित्तपोषण के पूरक हैं। 2023-24 और पिछली अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय के उद्देश्य से ईसीबी रूट के माध्यम से जुटाई गई निधियों से, 2023-24 के दौरान किए जाने वाले पूंजीगत व्यय को पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना से अधिक बढ़ाकर ₹1,16,073 करोड़ कर दिया गया। साथ ही, आईपीओ रूट के माध्यम से जुटाई गई निधियों से नियोजित पूंजीगत व्यय 2023-24 में बढ़कर ₹6,138 करोड़ हो गया, हालांकि कुल परिकल्पित पूंजीगत व्यय में इसका हिस्सा नगण्य रहा (अनुलग्नक सारणी ए 2 और ए3)।

कुल मिलाकर, निधियन के विभिन्न चैनलों के आधार पर, जैसा कि पहले बताया गया है, 2023-24 में निजी कॉरपोरेट क्षेत्र द्वारा कुल ₹4,03,186 करोड़ का पूंजी निवेश करने का इरादा था, जो पिछले वर्ष के दौरान नियोजित पूंजीगत व्यय से काफी अधिक (56.6 प्रतिशत) था, जिसका कारण बैंकों/एफआई द्वारा मंजूर परियोजनाओं के लिए कुल निधियों में वृद्धि और ईसीबी रूट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि थी। संदर्भ वर्ष से पहले पिछले वर्षों में बैंकों/एफआई द्वारा मंजूर पाइपलाइन परियोजनाओं [6] के आधार पर परिकल्पित पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध रूपरेखा यह संकेत देती है कि परिकल्पित पूंजी निवेश 2023-24 में ₹1,17,182 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹1,68,176 करोड़ होने की उम्मीद है; वित्तपोषण के सभी चैनलों को ध्यान में रखते हुए, कुल परिकल्पित पूंजी निवेश 2024-25 में ₹2,45,212 करोड़ होने का अनुमान है, जबकि 2023-24 में यह ₹1,59,221 करोड़ है (अनुलग्नक सारणी ए1 और ए4)।

## IV. निष्कर्ष

2023-24 के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के आधार पर निजी कॉरपोरेट्स के परिकल्पित पूंजी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि, निवेश चक्र में तेजी की ओर इशारा करती है। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत बढ़कर ₹3,90,978 करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। अवसंरचना क्षेत्र ने परिकल्पित पूंजी निवेश का बड़ा हिस्सा आकर्षित करना जारी रखा, जिसमें 'सड़क और पुल' तथा 'बिजली' क्षेत्रों की प्रमुखता रही, जो अवसंरचना विकास के प्रति सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। 2023-24 के दौरान परिकल्पित परियोजनाओं की कुल लागत में से, 54 प्रतिशत को वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक निवेश करने की योजना बनाई गई थी, 30 प्रतिशत 2024-25 के लिए प्रदान किया गया है और शेष 16 प्रतिशत को बाद के वर्षों में निवेश करने की परिकल्पना की गई है। तीनों चैनलों के माध्यम से पाइपलाइन परियोजनाओं के वित्तपोषण की चरणबद्ध रूपरेखा से पता चलता है कि परिकल्पित पूंजीगत व्यय 2023-24 में ₹1,59,221 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹2,45,212 करोड़ हो सकता है।

कॉरपोरेट और बैंकों दोनों का सुदृढ़ तुलन पत्र, कॉरपोरेट लाभप्रदता में सुधार, निरंतर ऋण मांग, बढ़ती क्षमता उपयोग और आरबीआई तथा अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए दूरदर्शी उद्यम सर्वेक्षणों में परिलक्षित कारोबारी भावनाओं में आशावाद, निजी कॉरपोरेट्स को आगे चलकर निवेश करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। यहाँ नकारात्मक पक्ष यह है कि वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता, लंबे समय तक भू-राजनीतिक तनाव और भू-आर्थिक विखंडन निवेश योजनाओं को कमजोर कर सकते हैं। कुल मिलाकर, निवेश चक्र के सकारात्मक बने रहने की उम्मीद है और इसकी स्थिरता पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है।

**संदर्भ:**

Rangarajan, C. (1970). Forecasting capital expenditure in the corporate sector. *Economic and Political Weekly, 5*(51), 2049-2051.

[6] पाइपलाइन परियोजनाएँ वे परियोजनाएँ हैं जो पहले से ही कार्यान्वयन के लिए शुरू की गई हैं। पाइपलाइन परियोजनाओं से पूंजीगत व्यय किसी दिए गए वर्ष के लिए परिकल्पित राशि है, जिसे उस दिए गए वर्ष से पहले स्वीकृत किया गया था।

## सारणी ए1: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध निर्धारण

| स्वीकृति का वर्ष ↓ | परियोजनाओं की संख्या | स्वीकृति वर्ष में परियोजना लागत (करोड़ रूपये में) | संशोधन/निरस्तीकरण के कारण परियोजना लागत^ (करोड़ रुपये में) | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2013-14 तक | | | | 1,70,603 | 93,658 | 34,172 | 14,421 | 4,722 |
| 2014-15 | 326 | 87,601 | 87,253 (0.4) | 14,920 | 34,589 | 25,765 | 9,535 | 1,246 |
| 2015-16 | 346 | 95,371 | 91,781 (3.8) | 3,787 | 7,434 | 37,517 | 28,628 | 8,079 |
| 2016-17 | 541 | 1,82,807 | 1,79,249 (2.0) | 1,352 | 3,952 | 25,388 | 71,186 | 41,075 |
| 2017-18 | 485 | 1,72,831 | 1,68,239 (2.6) | | 620 | 15,184 | 12,445 | 63,001 |
| 2018-19 | 409 | 1,76,581 | 1,59,189 (9.8) | | | 569 | 6,862 | 11,000 |
| 2019-20 | 320 | 2,00,038 | 1,75,830 (12.1) | | | | | 4,049 |
| 2020-21 | 220 | 75,558 | 75,558 (0.0) | | | | | |
| 2021-22 | 401 | 1,43,314 | 1,41,976 (0.9) | | | | | |
| 2022-23 | 547 | 2,66,547 | 2,66,546 (0.0) | | | | | |
| 2023-24 | 944 | 3,90,978 | | | | | | |
| **कुल योग &** | | | | **1,90,662** | **1,40,253** | **1,38,595** | **1,43,077** | **1,33,172** |
| **प्रतिशत परिवर्तन** | | | | | **-26.4** | **-1.2** | **3.2** | **-6.9** |

## सारणी ए1: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध निर्धारण *(जारी)*

| स्वीकृति का वर्ष ↓ | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2024-25 से आगे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2013-14 तक | 1,472 | | | | | | | |
| 2014-15 | 162 | 1,036 | | | | | | |
| 2015-16 | 4,964 | 1,152 | 220 | | | | | |
| 2016-17 | 21,643 | 8,566 | 4,001 | 2,086 | | | | |
| 2017-18 | 41,436 | 22,767 | 10,202 | 2,342 | 242 | | | |
| 2018-19 | 59,973 | 47,080 | 21,248 | 9,759 | 2,663 | 35 | | |
| 2019-20 | 14,524 | 53,978 | 58,556 | 28,116 | 14,114 | 2,299 | 194 | |
| 2020-21 | 2,491 | 3,709 | 29,013 | 26,166 | 9,711 | 3,867 | 601 | |
| 2021-22 | | 3,610 | 10,543 | 59,622 | 44,176 | 18,442 | 3,541 | 2,042 |
| 2022-23 | | 1,127 | 2,150 | 16,663 | 87,997 | 92,539 | 47,912 | 18,158 |
| 2023-24 | | | 2,235 | 6,783 | 39,455 | 1,63,793 | 1,15,928 | 62,783 |
| **कुल योग &** | **1,46,665** | **1,43,025** | **1,38,168** | **1,51,537** | **1,98,358** | **2,80,975** | **1,68,176** | **82,983** |
| **प्रतिशत परिवर्तन** | **10.1** | **-2.5** | **-3.4** | **9.7** | **30.9** | **41.7** | **#** | |

&: कॉलम योग किसी विशेष वर्ष में परिकल्पित पूंजीगत व्यय को दर्शाता है जिसमें विभिन्न वर्षों में वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाएं शामिल हैं। अनुमान पूर्व-निर्धारित है जिसमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल हैं। वे वास्तव में प्राप्त/उपयोग किए गए निवेशों से भिन्न हैं।

#: 2024-25 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2024-25 में स्वीकृत होने वाले प्रस्ताव से पूंजीगत व्यय अभी उपलब्ध नहीं है।

^: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संशोधन/निरस्तीकरण का प्रतिशत हैं।

**सारणी ए2: ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी के माध्यम से वित्तपोषित पूंजीगत व्यय परियोजनाओं का चरणबद्ध वर्गीकरण***

| स्वीकृति का वर्ष ↓ | जारी किए गए एलआरएन की संख्या | कुल ऋण स्वीकृत (₹ करोड़) | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2013-14 तक | | | 78,864 | 27,376 | 4,896 | | | |
| 2014-15 | 478 | 57,327 | | 36,791 | 16,806 | 3,151 | 575 | 2 |
| 2015-16 | 314 | 38,885 | | | 28,998 | 7,311 | 2,572 | 4 |
| 2016-17 | 346 | 22,154 | | | | 14,953 | 6,005 | 1,192 |
| 2017-18 | 419 | 37,896 | | | | | 17,822 | 13,054 |
| 2018-19 | 515 | 72,490 | | | | | | 46,221 |
| 2019-20 | 495 | 95,491 | | | | | | |
| 2020-21 | 362 | 40,564 | | | | | | |
| 2021-22 | 363 | 51,059 | | | | | | |
| 2022-23 | 393 | 81,101 | | | | | | |
| 2023-24 | 438 | 1,68,396 | | | | | | |
| **कुल योग &** | | | **78,864** | **64,167** | **50,700** | **25,415** | **26,974** | **60,473** |
| **प्रतिशत परिवर्तन** | | | | **-18.6** | **-21.0** | **-49.9** | **6.1** | **124.2** |

**सारणी ए2: ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी के माध्यम से वित्तपोषित पूंजीगत व्यय परियोजनाओं का चरणबद्ध वर्गीकरण*** *(जारी)*

| स्वीकृति का वर्ष ↓ | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2024-25 से आगे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2013-14 तक | | | | | | | |
| 2014-15 | 2 | | | | | | |
| 2015-16 | | | | | | | |
| 2016-17 | 2 | 2 | | | | | |
| 2017-18 | 6,484 | 529 | 7 | | | | |
| 2018-19 | 17,725 | 1,236 | 5,398 | 1,844 | 66 | | |
| 2019-20 | 65,367 | 17,157 | 11,717 | 965 | 285 | | |
| 2020-21 | | 21,865 | 13,574 | 3,219 | 1,675 | 231 | |
| 2021-22 | | 13 | 29,315 | 16,554 | 5,089 | 89 | |
| 2022-23 | | | | 33,927 | 31,785 | 14,438 | 950 |
| 2023-24 | | | | 32 | 77,173 | 59,287 | 31,904 |
| **कुल योग &** | **89,580** | **40,802** | **60,011** | **56,542** | **1,16,073** | **74,045** | **32,854** |
| **प्रतिशत परिवर्तन** | **48.1** | **-54.5** | **47.1** | **-5.8** | **105.3** | **#** | |

*: वे परियोजनाएँ जिन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सहायता नहीं मिली।
**: रुपया मूल्यवर्गित बॉण्ड (आरडीबी) को 2016-17 से शामिल किया गया है।
#: 2024-25 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2024-25 में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों से पूंजीगत व्यय अभी उपलब्ध नहीं है।
&: अनुमान केवल अनुमानित निवेश को शामिल करते हुए पूर्व-निर्धारित है। वे वास्तव में प्राप्त/उपयोग किए गए निवेश से भिन्न हैं।
एलआरएन : ऋण पंजीकरण संख्या।

## सारणी ए3: इक्विटी निर्गमों के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध निर्धारण*

| ↓ के दौरान जारी की गई इक्विटी | कम्पनियों की संख्या | अनुमानित पूंजी व्यय (करोड़ रुपये) | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2013-14 तक | | | 494 | 492 | 70 | | | |
| 2014-15 | 24 | 1,078 | | 189 | 557 | 332 | | |
| 2015-16 | 40 | 4,511 | | 11 | 644 | 2,753 | 849 | 183 |
| 2016-17 | 29 | 1,159 | | | 14 | 471 | 368 | 163 |
| 2017-18 | 51 | 1,538 | | | | | 419 | 327 |
| 2018-19 | 39 | 609 | | | | | | 506 |
| 2019-20 | 12 | 53 | | | | | | 2 |
| 2020-21 | 12 | 663 | | | | | | |
| 2021-22 | 27 | 3,410 | | | | | | |
| 2022-23 | 42 | 3,629 | | | | | | |
| 2023-24 | 123 | 6,310 | | | | | | |
| **कुल योग &** | | | **494** | **692** | **1,285** | **3,556** | **1,636** | **1,181** |
| **प्रतिशत परिवर्तन** | | | | **40.1** | **85.7** | **176.7** | **-54.0** | **-27.8** |

## सारणी ए3: इक्विटी निर्गमों के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध निर्धारण* *(जारी)*

| ↓ के दौरान जारी की गई इक्विटी | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2024-25 से आगे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2013-14 तक | | | | | | | |
| 2014-15 | | | | | | | |
| 2015-16 | 71 | | | | | | |
| 2016-17 | 143 | | | | | | |
| 2017-18 | 787 | 5 | | | | | |
| 2018-19 | 90 | 13 | | | | | |
| 2019-20 | 49 | 2 | | | | | |
| 2020-21 | | 139 | 421 | 84 | 19 | | |
| 2021-22 | | 10 | 757 | 1,304 | 939 | 400 | |
| 2022-23 | | | | 1,172 | 2,181 | 276 | |
| 2023-24 | | | | 58 | 2,999 | 2,316 | 937 |
| **कुल योग &** | **1,140** | **169** | **1,178** | **2,618** | **6,138** | **2,992** | **937** |
| **प्रतिशत परिवर्तन** | **-3.5** | **-85.2** | **597.0** | **122.2** | **134.4** | **#** | |

*: वे परियोजनाएँ जिन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी से सहायता नहीं मिली।
#: 2024-25 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2024-25 में लागू होने वाले प्रस्तावों से पूंजीगत व्यय अभी उपलब्ध नहीं है।
&: अनुमान पूर्व-निर्धारित है जिसमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल है, वे वास्तव में प्राप्त/उपयोग किए गए निवेश से भिन्न हैं।

**सारणी ए4: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/आईपीओ/ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी*/आईपीओ के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध वर्गीकरण**

| स्वीकृति का वर्ष ↓ | कंपनियों या बैंकों/ एफआई/ईसीबी/ एफसीसीबी/ आरडीबी/आईपीओ की संख्या | परियोजना लागत (करोड़ रुपये) | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2013-14 तक | | | 2,49,961 | 1,21,526 | 39,138 | 14421 | 4722 | 1472 |
| 2014-15 | 828 | 1,45,658 | 14920 | 71,569 | 43,128 | 13,018 | 1821 | 164 |
| 2015-16 | 700 | 1,35,177 | 3787 | 7445 | 67,159 | 38,692 | 11,500 | 5151 |
| 2016-17 | 916 | 2,02,562 | 1352 | 3952 | 25402 | 86,610 | 47,448 | 22,998 |
| 2017-18 | 955 | 2,07,673 | | 620 | 15184 | 12445 | 81,242 | 54,817 |
| 2018-19 | 963 | 2,32,288 | | | 569 | 6862 | 11000 | 1,06,700 |
| 2019-20 | 827 | 2,71,374 | | | | | 4049 | 14526 |
| 2020-21 | 594 | 1,16,785 | | | | | | 2491 |
| 2021-22 | 791 | 1,96,445 | | | | | | |
| 2022-23 | 982 | 3,51,276 | | | | | | |
| 2023-24 | 1,505 | 5,65,684 | | | | | | |
| **कुल योग &** | | | **2,70,020** | **2,05,112** | **1,90,580** | **1,72,048** | **1,61,782** | **2,08,319** |
| **प्रतिशत परिवर्तन** | | | | **-24.0** | **-7.1** | **-9.7** | **-6.0** | **28.8** |

**सारणी A4: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/आईपीओ/ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी*/आईपीओ के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध वर्गीकरण** *(जारी)*

| स्वीकृति का वर्ष ↓ | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2024-25 से आगे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2013-14 तक | | | | | | | |
| 2014-15 | 1038 | | | | | | |
| 2015-16 | 1223 | 220 | | | | | |
| 2016-17 | 8711 | 4003 | 2086 | | | | |
| 2017-18 | 30,038 | 10736 | 2349 | 242 | | | |
| 2018-19 | 64,895 | 22,497 | 15,157 | 4,507 | 101 | | |
| 2019-20 | 1,19,394 | 75,715 | 39,833 | 15079 | 2584 | 194 | |
| 2020-21 | 3709 | 51,017 | 40,161 | 13,014 | 5,561 | 832 | |
| 2021-22 | 3610 | 10566 | 89,694 | 62,034 | 24,470 | 4030 | 2,042 |
| 2022-23 | 1127 | 2150 | 16663 | 1,23,096 | 1,26,505 | 62,626 | 19,108 |
| 2023-24 | | 2,235 | 6,783 | 39,545 | 2,43,965 | 1,77,531 | 95,624 |
| **कुल योग &** | **2,33,745** | **1,79,139** | **2,12,726** | **2,57,518** | **4,03,186** | **2,45,212** | **1,16,774** |
| **प्रतिशत परिवर्तन** | **12.2** | **-23.4** | **18.7** | **21.1** | **56.6** | **#** | |

*: रुपया मूल्यवर्गित बांड (आरडीबी) को 2016-17 से शामिल किया गया है।
#: 2024-25 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है, क्योंकि 2024-25 में स्वीकृत किए जाने वाले प्रस्तावों से पूंजीगत व्यय अभी उपलब्ध नहीं है।
&: अनुमान पूर्व-निर्धारित है, जिसमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल है, वे वास्तव में प्राप्त/उपयोग किए गए निवेश से भिन्न हैं।

## सारणी ए5: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का आकार-वार वितरण: 2013-14 से 2023-24

| अवधि | परियोजनाओं की संख्या और हिस्सेदारी | ₹100 करोड़ से कम | ₹100 करोड़ से ₹500 करोड़ | ₹500 करोड़ से ₹1000 करोड़ | ₹1000 करोड़ से ₹5000 करोड़ | ₹5000 करोड़ और उससे अधिक | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | परियोजनाओं की संख्या | 306 | 115 | 25 | 21 | 5 | **472** |
| | प्रतिशत हिस्सा | 8.3 | 20 | 13.9 | 29.1 | 28.7 | **100 (1,27,328)** |
| 2014-15 | परियोजनाओं की संख्या | 223 | 65 | 18 | 19 | 1 | **326** |
| | प्रतिशत हिस्सा | 9 | 16.6 | 14.6 | 47.8 | 12 | **100 (87,253)** |
| 2015-16 | परियोजनाओं की संख्या | 214 | 76 | 34 | 21 | 1 | **346** |
| | प्रतिशत हिस्सा | 8.6 | 20.9 | 26 | 38.5 | 5.9 | **100 (91,781)** |
| 2016-17 | परियोजनाओं की संख्या | 287 | 180 | 29 | 40 | 5 | **541** |
| | प्रतिशत हिस्सा | 5.8 | 23.3 | 11.9 | 41.7 | 17.4 | **100 (1,79,239)** |
| 2017-18 | परियोजनाओं की संख्या | 263 | 149 | 28 | 42 | 3 | **485** |
| | प्रतिशत हिस्सा | 5.2 | 21 | 10.8 | 43.8 | 19.1 | **100 (1,68,239)** |
| 2018-19 | परियोजनाओं की संख्या | 220 | 110 | 39 | 36 | 4 | **409** |
| | प्रतिशत हिस्सा | 4.8 | 17 | 17 | 39.6 | 21.6 | **100 (1,59,189)** |
| 2019-20 | परियोजनाओं की संख्या | 150 | 84 | 45 | 36 | 5 | **320** |
| | प्रतिशत हिस्सा | 3.3 | 11.9 | 18.6 | 37.4 | 28.8 | **100 (1,75,830)** |
| 2020-21 | परियोजनाओं की संख्या | 128 | 52 | 15 | 24 | 1 | **220** |
| | प्रतिशत हिस्सा | 5.5 | 16.8 | 14.2 | 53.5 | 10 | **100 (75,558)** |
| 2021-22 | परियोजनाओं की संख्या | 200 | 127 | 36 | 36 | 2 | **401** |
| | प्रतिशत हिस्सा | 5.6 | 20.0 | 19.6 | 46.9 | 7.9 | **100 (1,41,976)** |
| 2022-23 | परियोजनाओं की संख्या | 264 | 156 | 51 | 68 | 8 | **547** |
| | प्रतिशत हिस्सा | 3.9 | 13.6 | 14.1 | 41.3 | 27.1 | **100 (2,66,546)** |
| 2023-24 | परियोजनाओं की संख्या | 484 | 265 | 107 | 77 | 11 | **944** |
| | प्रतिशत हिस्सा | 4.6 | 16.6 | 20.0 | 37.1 | 21.7 | **100 (3,90,978)** |

**टिप्पणी:** i. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े परियोजनाओं की कुल लागत ₹ करोड़ में हैं।
ii. प्रतिशत हिस्सा परियोजनाओं की कुल लागत में हिस्सा है। पूर्णांकन के कारण प्रतिशत का योग 100 नहीं हो सकता है।

## सारणी ए6: 2013-14 से 2023-24 के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का उद्देश्य-वार वितरण

| अवधि | परियोजनाओं की संख्या और हिस्सेदारी | नया | विस्तार और आधुनिकीकरण | विविधता | अन्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | परियोजनाओं की संख्या | 361 | 95 | 2 | 14 | **472** |
| | प्रतिशत हिस्सा | 65.2 | 20.1 | - | 14.7 | **100 (1,27,328)** |
| 2014-15 | परियोजनाओं की संख्या | 203 | 92 | 2 | 29 | **326** |
| | प्रतिशत हिस्सा | 39.4 | 14.7 | 0.2 | 45.7 | **100 (87,253)** |
| 2015-16 | परियोजनाओं की संख्या | 260 | 64 | 3 | 19 | **346** |
| | प्रतिशत हिस्सा | 73.6 | 14.3 | 0.1 | 12.0 | **100 (91,781)** |
| 2016-17 | परियोजनाओं की संख्या | 429 | 97 | 4 | 11 | **541** |
| | प्रतिशत हिस्सा | 78.6 | 9.9 | 0.1 | 11.3 | **100 (1,79,249)** |
| 2017-18 | परियोजनाओं की संख्या | 396 | 80 | 2 | 7 | **485** |
| | प्रतिशत हिस्सा | 89.0 | 9.5 | 0.1 | 1.5 | **100 (1,68,239)** |
| 2018-19 | परियोजनाओं की संख्या | 309 | 80 | - | 20 | **409** |
| | प्रतिशत हिस्सा | 76.8 | 19.3 | - | 3.9 | **100 (1,59,189)** |
| 2019-20 | परियोजनाओं की संख्या | 262 | 37 | 1 | 20 | **320** |
| | प्रतिशत हिस्सा | 79.8 | 13.7 | - | 6.4 | **100 (1,75,830)** |
| 2020-21 | परियोजनाओं की संख्या | 181 | 38 | 1 | - | **220** |
| | प्रतिशत हिस्सा | 94.1 | 5.9 | - | - | **100 (75,558)** |
| 2021-22 | परियोजनाओं की संख्या | 312 | 88 | 1 | - | **401** |
| | प्रतिशत हिस्सा | 89.1 | 10.8 | 0.1 | - | **100 (1,41,976)** |
| 2022-23 | परियोजनाओं की संख्या | 440 | 101 | - | 6 | **547** |
| | प्रतिशत हिस्सा | 93.1 | 6.1 | - | 0.8 | **100 (2,66,546)** |
| 2023-24 | परियोजनाओं की संख्या | 767 | 167 | 4 | 6 | **944** |
| | प्रतिशत हिस्सा | 89.1 | 8.6 | 0.1 | 2.2 | **100 (3,90,978)** |

**टिप्पणी:** i. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े परियोजनाओं की कुल लागत ₹ करोड़ में हैं।
ii. प्रतिशत हिस्सा परियोजनाओं की कुल लागत में हिस्सा है। पूर्णांकन के कारण प्रतिशत का योग 100 नहीं हो सकता।
iii. -: शून्य/नगण्य।

## सारणी ए7: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का उद्योगवार वितरण : 2013-14 से 2023-24

| उद्योग | 2013-14 | | 2014-15 | | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत हिस्सा | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत हिस्सा | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत हिस्सा | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत हिस्सा | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत हिस्सा | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत हिस्सा |
| आधारभूत संरचना | 87 | 39.7 | 74 | 48.9 | 108 | 72 | 204 | 62.5 | 150 | 51.7 | 122 | 60.3 |
| i) पावर | 70 | 35.1 | 65 | 42.2 | 92 | 57.1 | 170 | 45.4 | 117 | 36.5 | 78 | 26.8 |
| ii) दूरसंचार | 1 | - | 1 | 4.9 | 1 | 0.3 | 1 | - | - | - | - | - |
| iii) बंदरगाह और हवाई अड्डे | 1 | 0.8 | - | - | 3 | 2.4 | 8 | 5.7 | 6 | 3.1 | 4 | 14.2 |
| iv) भंडारण एवं जल प्रबंधन | 5 | 1.1 | 2 | 0.6 | 4 | 4.2 | 6 | 3.7 | 2 | 0.4 | 13 | 5.7 |
| v) एसईजेड, औद्योगिक, बायोटेक और आईटी पार्क | 8 | 1.5 | 3 | 0.9 | 1 | 0.4 | 2 | 0.4 | 9 | 1.6 | 11 | 3.2 |
| vi) सड़कें और पुल | 2 | 1.2 | 3 | 0.3 | 7 | 7.6 | 17 | 7.3 | 16 | 10.1 | 16 | 10.4 |
| धातु एवं धातु उत्पाद | 44 | 17.4 | 17 | 17.4 | 14 | 1.5 | 23 | 4.9 | 21 | 9.7 | 16 | 3 |
| निर्माण | 27 | 2.1 | 29 | 4 | 26 | 1.8 | 60 | 12 | 39 | 5.3 | 26 | 2.3 |
| इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स | 9 | 2 | 7 | 0.2 | 2 | 0.2 | 9 | 0.2 | 6 | 0.2 | 1 | 0.1 |
| खाद्य उत्पाद | 43 | 1.8 | 34 | 2.9 | 26 | 1.8 | 38 | 0.9 | 47 | 2.8 | 28 | 1.4 |
| रसायन एवं कीटनाशक | 15 | 1 | 7 | 2.6 | 11 | 1.6 | 10 | 2.1 | 23 | 11.4 | 19 | 2.9 |
| वस्त्र | 58 | 10.3 | 50 | 4.1 | 49 | 4.8 | 57 | 4.1 | 54 | 3.7 | 27 | 3.4 |
| परिवहन सेवाएं | 14 | 0.5 | 5 | 0.6 | 10 | 1.2 | 12 | 0.4 | 16 | 4.1 | 5 | 0.2 |
| कोक और पेट्रोलियम उत्पाद | 1 | 0.5 | 1 | 3.4 | 2 | 2.0 | 2 | 0.5 | 1 | 0.4 | - | - |
| सीमेंट | 12 | 7.1 | 7 | 3.8 | 5 | 1.9 | 5 | 2.3 | 3 | 0.6 | 10 | 5.1 |
| परिवहन उपकरण और कलपुर्ज़े | 14 | 1.0 | 7 | 5.3 | 4 | 2.5 | 9 | 3.6 | 10 | 0.3 | 5 | 0.8 |
| खनन और उत्खनन | 1 | 0.6 | 2 | 0.1 | 10 | 2.7 | 4 | 0.4 | 1 | - | - | - |
| होटल और रेस्तरां | 22 | 2.2 | 15 | 1.1 | 16 | 1.1 | 12 | 0.8 | 29 | 2.9 | 26 | 1.9 |
| दवाइयों | 19 | 1.3 | 9 | 1.5 | 11 | 0.3 | 12 | 1.1 | 15 | 0.6 | 23 | 1.6 |
| अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवाएं | 10 | 0.7 | 2 | 0.1 | 1 | - | 22 | 1.1 | 18 | 1.8 | 15 | 2.6 |
| रबर और प्लास्टिक उत्पाद | 9 | 0.3 | 8 | 0.8 | 4 | 0.5 | 8 | 0.2 | 10 | 2.5 | 5 | 0.5 |
| आईटी सॉफ्टवेयर | 3 | 0.1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 0.7 |
| अन्य* | 84 | 11.4 | 51 | 3.2 | 46 | 4.1 | 54 | 2.9 | 41 | 2.0 | 79 | 13.3 |
| **कुल** | **472** | **100** | **326** | **100** | **346** | **100** | **541** | **100** | **485** | **100** | **409** | **100** |
| **कुल परियोजना लागत ₹ करोड़ में** | **1,27,328** | | **87,253** | | **91,781** | | **1,79,249** | | **1,68,239** | | **1,59,189** | |

*: इसमें कागज़ और कागज़ उत्पाद, कृषि और संबंधित गतिविधियाँ, बिजली और गैर-बिजली मशीनरी का विनिर्माण, कांच और मिट्टी के बर्तन, चीनी और संबद्ध उत्पाद, मनोरंजन, सेवाओं का व्यापार, मुद्रण और प्रकाशन, अन्य विनिर्माण और अन्य सेवाएँ जैसे उद्योग शामिल हैं।

**नोट:** i. प्रतिशत हिस्सा परियोजना की कुल लागत में हिस्सा है। पूर्णांकन के कारण प्रतिशत का योग 100 नहीं हो सकता।

ii. -: शून्य/नगण्य।

**सारणी ए7: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का उद्योगवार वितरण : 2013-14 से 2023-24** *(जारी)*

| उद्योग | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत हिस्सा | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत हिस्सा | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत हिस्सा | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत हिस्सा | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत हिस्सा |
| आधारभूत संरचना | 99 | 61.5 | 63 | 74.3 | 95 | 56.4 | 135 | 59.9 | 245 | 55.5 |
| i) पावर | 47 | 32.9 | 35 | 49.3 | 58 | 29 | 53 | 20.3 | 139 | 24.4 |
| ii) दूरसंचार | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.6 |
| iii) बंदरगाह और हवाई अड्डे | 4 | 8.4 | 1 | 0.1 | 2 | 5.9 | 2 | 0.4 | 9 | 4.8 |
| iv) भंडारण एवं जल प्रबंधन | 4 | 0.4 | 5 | 1.2 | 2 | 0.2 | 3 | 0.8 | 4 | 0.0 |
| v) एसईजेड, औद्योगिक, बायोटेक और आईटी पार्क | 8 | 1.3 | 5 | 2.2 | 3 | 1.1 | 8 | 1.9 | 10 | 0.5 |
| vi) सड़कें और पुल | 36 | 18.5 | 17 | 21.5 | 30 | 20.2 | 69 | 36.5 | 82 | 25.2 |
| धातु एवं धातु उत्पाद | 14 | 0.8 | 6 | 0.8 | 27 | 4.2 | 60 | 14.6 | 71 | 9.3 |
| विनिर्माण | 44 | 11.4 | 27 | 4.8 | 22 | 7.4 | 35 | 4 | 56 | 8.0 |
| इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स | 4 | - | 1 | 0.1 | 5 | 4 | 9 | 1.1 | 15 | 4.4 |
| खाद्य उत्पाद | 32 | 1.9 | 20 | 1.5 | 25 | 1.8 | 40 | 2.5 | 107 | 3.0 |
| रसायन एवं कीटनाशक | 12 | 1.3 | 9 | 1.6 | 20 | 3.4 | 16 | 2.3 | 33 | 2.9 |
| वस्त्र | 11 | 0.5 | 15 | 1.8 | 56 | 4.5 | 42 | 2.8 | 58 | 2.2 |
| परिवहन सेवाएं | 14 | 1.4 | 1 | 0.1 | 18 | 2.4 | 21 | 0.6 | 35 | 2.1 |
| कोक और पेट्रोलियम उत्पाद | 3 | 8.0 | - | - | 7 | 1.0 | 17 | 1.1 | 28 | 1.6 |
| सीमेंट | 2 | 0.1 | 5 | 1.3 | 3 | 3.3 | 2 | 0.8 | 11 | 1.3 |
| परिवहन उपकरण और कलपुर्ज़े | 5 | 0.4 | 2 | 0.3 | 5 | 0.4 | 16 | 0.6 | 12 | 1.2 |
| खनन और उत्खनन | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 7 | 1.8 | 11 | 1.2 |
| होटल और रेस्तरां | 16 | 1.7 | 4 | 2.9 | 12 | 0.9 | 13 | 0.4 | 58 | 1.1 |
| दवाइयों | 9 | 0.6 | 7 | 0.5 | 20 | 1.3 | 30 | 2.1 | 29 | 0.8 |
| अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवाएं | 12 | 0.7 | 7 | 0.3 | 19 | 2.3 | 20 | 1.1 | 25 | 0.7 |
| रबर और प्लास्टिक उत्पाद | 5 | 0.3 | 17 | 2.1 | 12 | 0.8 | 13 | 0.8 | 24 | 0.7 |
| आईटी सॉफ्टवेयर | 1 | - | - | - | 2 | 0.6 | 4 | 1.2 | 4 | 0.6 |
| अन्य* | 37 | 9.3 | 36 | 7.6 | 52 | 5.2 | 67 | 2.3 | 122 | 3.5 |
| **कुल** | **320** | **100** | **220** | **100** | **401** | **100** | **547** | **100** | **944** | **100** |
| **कुल परियोजना लागत ₹ करोड़ में** | **1,75,830** | | **75,558** | | **1,41,976** | | **2,66,546** | | **3,90,978** | |

*: इसमें कागज़ और कागज़ उत्पाद, कृषि और संबंधित गतिविधियाँ, बिजली और गैर-बिजली मशीनरी का विनिर्माण, कांच और मिट्टी के बर्तन, चीनी और संबद्ध उत्पाद, मनोरंजन, सेवाओं का व्यापार, मुद्रण और प्रकाशन, अन्य विनिर्माण और अन्य सेवाएँ जैसे उद्योग शामिल हैं।

**नोट:** i. प्रतिशत हिस्सा परियोजना की कुल लागत में हिस्सा है। पूर्णांकन के कारण प्रतिशत का योग 100 नहीं हो सकता।

ii. -: शून्य/नगण्य।

## सारणी ए8: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार वितरण: 2013-14 से 2023-24

| राज्य | 2013-14 | | 2014-15 | | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत हिस्सा | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत हिस्सा | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत हिस्सा | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत हिस्सा | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत हिस्सा | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत हिस्सा |
| गुजरात | 66 | 14.5 | 71 | 9.5 | 61 | 15.1 | 102 | 23 | 71 | 8 | 56 | 11.1 |
| महाराष्ट्र | 76 | 19.7 | 38 | 14.8 | 36 | 9.4 | 57 | 8.8 | 65 | 23.3 | 34 | 11.5 |
| कर्नाटक | 39 | 6.2 | 27 | 5.4 | 21 | 6.2 | 52 | 6.8 | 64 | 9.6 | 34 | 5.7 |
| आंध्र प्रदेश | 37 | 4 | 24 | 8.1 | 33 | 12.3 | 47 | 8 | 22 | 9.9 | 29 | 11.1 |
| उत्तर प्रदेश | 21 | 1.1 | 20 | 5.4 | 15 | 2.5 | 22 | 3.7 | 30 | 2.4 | 28 | 4.8 |
| ओडिशा | 10 | 11.7 | 5 | 15.9 | 6 | 3.1 | 6 | 3.1 | 5 | 3 | 9 | 1.4 |
| तेलंगाना | - | - | - | - | 10 | 3.8 | 51 | 5.5 | 17 | 1.9 | 26 | 9.1 |
| राजस्थान | 24 | 1.4 | 29 | 11.1 | 10 | 0.9 | 23 | 2.8 | 33 | 6.3 | 21 | 7.7 |
| झारखंड | 4 | 0.3 | 2 | 0.7 | 5 | 0.3 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | 2 | 0.5 |
| मध्य प्रदेश | 30 | 6.1 | 14 | 3.9 | 21 | 7.0 | 18 | 7.5 | 10 | 0.7 | 12 | 1.6 |
| छत्तीसगढ | 16 | 10.7 | 8 | 7.4 | 8 | 4.6 | 15 | 4.0 | 7 | 4.8 | 6 | 0.9 |
| तमिलनाडु | 33 | 5.4 | 27 | 2.9 | 26 | 9.3 | 23 | 4.4 | 28 | 6.6 | 32 | 12.8 |
| बिहार | 6 | 0.2 | 4 | 0.1 | 6 | 0.2 | 4 | 0.2 | 3 | 0.1 | 6 | 0.4 |
| पश्चिम बंगाल | 12 | 1.2 | 9 | 1.3 | 14 | 3.1 | 18 | 1.7 | 14 | 1.8 | 13 | 1.1 |
| जम्मू और कश्मीर | 10 | 5.2 | 2 | 0.1 | 9 | 0.2 | 3 | 0.1 | 8 | 2.0 | 11 | 0.4 |
| पंजाब | 28 | 1.5 | 6 | 0.3 | 11 | 1.7 | 29 | 2.1 | 31 | 2.2 | 15 | 1.9 |
| हरियाणा | 15 | 1.1 | 11 | 1.9 | 16 | 3.6 | 13 | 1.6 | 21 | 0.5 | 18 | 1.7 |
| दिल्ली | 5 | 0.4 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 6 | 1.2 | 8 | 1.3 |
| असम | 4 | 0.3 | 2 | 0.2 | 4 | 0.4 | 10 | 0.6 | 5 | 0.8 | 4 | 0.2 |
| हिमाचल प्रदेश | 3 | 1.8 | 3 | 0.1 | 8 | 1.4 | 1 | 0.0 | 8 | 2.3 | 7 | 0.3 |
| केरल | 3 | 0.0 | 4 | 0.2 | 4 | 0.1 | 6 | 2.7 | 3 | 0.1 | 6 | 0.9 |
| गोवा | - | - | - | - | 1 | 0.0 | 3 | 0.6 | 2 | 1.9 | 3 | 1.8 |
| उत्तराखंड | 5 | 0.1 | 5 | 0.2 | 2 | 0.1 | 11 | 0.4 | 6 | 0.4 | 9 | 0.4 |
| बहु-राज्य # | 21 | 6.9 | 10 | 9.5 | 13 | 13.5 | 17 | 11.8 | 16 | 7.5 | 15 | 9.8 |
| अन्य* | 4 | 0.2 | 3 | 0.9 | 5 | 1.1 | 4 | 0.3 | 7 | 2.4 | 5 | 1.7 |
| **कुल** | 472 | 100 | 326 | 100 | 346 | 100 | 541 | 100 | 485 | 100 | 409 | 100 |
| **परियोजनाओं की कुल लागत (करोड़ रुपये में)** | **1,27,328** | | **87,253** | | **91,781** | | **1,79,249** | | **1,68,239** | | **1,59,189** | |

**सारणी ए8: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार वितरण: 2013-14 से 2023-24** *(जारी)*

| राज्य | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत हिस्सा | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत हिस्सा | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत हिस्सा | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत हिस्सा | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत हिस्सा |
| गुजरात | 47 | 15.1 | 54 | 17.1 | 82 | 11.7 | 82 | 14.0 | 154 | 14.7 |
| महाराष्ट्र | 41 | 6.9 | 13 | 8.5 | 44 | 9.7 | 48 | 7.9 | 93 | 11.7 |
| कर्नाटक | 33 | 17.2 | 11 | 6.1 | 24 | 6.9 | 37 | 7.3 | 61 | 11.1 |
| आंध्र प्रदेश | 12 | 4 | 7 | 15 | 11 | 2.1 | 27 | 4.4 | 51 | 10.1 |
| उत्तर प्रदेश | 24 | 5.4 | 30 | 13.7 | 33 | 12.8 | 45 | 16.2 | 69 | 7.6 |
| ओडिशा | 6 | 1.9 | 2 | 0.1 | 9 | 2.2 | 12 | 11.8 | 23 | 6.7 |
| तेलंगाना | 12 | 4 | 9 | 1.9 | 16 | 3.4 | 30 | 1.9 | 40 | 4.1 |
| राजस्थान | 23 | 3.8 | 21 | 17.1 | 32 | 12.6 | 22 | 3.1 | 61 | 3.6 |
| झारखंड | 4 | 9.4 | 1 | 0.2 | 6 | 0.8 | 12 | 1.9 | 17 | 3.4 |
| मध्य प्रदेश | 10 | 1.2 | 19 | 2.8 | 18 | 4.2 | 35 | 5.0 | 56 | 3.4 |
| छत्तीसगढ | 6 | 0.2 | 3 | 1.2 | 4 | 0.8 | 8 | 1.4 | 26 | 3.3 |
| तमिलनाडु | 28 | 8.3 | 7 | 0.7 | 40 | 8.8 | 44 | 4.8 | 83 | 3.0 |
| बिहार | 6 | 3.4 | 1 | 0 | 5 | 3.4 | 6 | 1.6 | 13 | 2.6 |
| पश्चिम बंगाल | 7 | 0.9 | 3 | 0.4 | 11 | 2.6 | 16 | 1.0 | 28 | 2.3 |
| जम्मू और कश्मीर | 3 | 0.3 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 23 | 3.1 | 36 | 1.9 |
| पंजाब | 9 | 0.8 | 4 | 0.7 | 15 | 2.1 | 21 | 2.5 | 34 | 1.6 |
| हरियाणा | 20 | 3.4 | 15 | 7.8 | 14 | 2.0 | 14 | 1.0 | 25 | 1.5 |
| दिल्ली | 3 | 0.5 | 2 | 0.1 | 3 | 0.6 | 12 | 0.4 | 10 | 1.2 |
| असम | 1 | 0.3 | 3 | 4.4 | 2 | 0.0 | 6 | 0.7 | 13 | 0.9 |
| हिमाचल प्रदेश | 6 | 0.1 | 4 | 0.2 | 7 | 1.2 | 11 | 2.2 | 10 | 0.3 |
| केरल | 3 | 1.0 | - | - | 5 | 4.2 | 12 | 0.9 | 11 | 0.2 |
| गोवा | 2 | 0.1 | - | - | 3 | 3.0 | 3 | 0.8 | 4 | 0.1 |
| उत्तराखंड | 5 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.4 | 5 | 0.2 | 8 | 0.1 |
| बहु-राज्य # | 8 | 11.7 | 2 | 1.4 | 7 | 4.0 | 10 | 5.5 | 12 | 4.4 |
| अन्य* | 1 | 0.0 | 2 | 0.3 | 3 | 0.3 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 |
| **कुल** | 320 | 100 | 220 | 100 | 401 | 100 | 547 | 100 | 547 | 100 |
| **परियोजनाओं की कुल लागत (करोड़ रुपये में)** | **1,75,830** | | **75,558** | | **1,41,976** | | **2,66,546** | | **3,90,978** | |

#: इसमें कई राज्यों की परियोजनाएँ शामिल हैं।
*: इसमें शेष राज्य/संघ शासित प्रदेश शामिल हैं।
**टिप्पण:** i. प्रतिशत हिस्सा परियोजना की कुल लागत में हिस्सा है। पूर्णांकन के कारण प्रतिशत का योग 100 नहीं हो सकता।
ii. -: शून्य/नगण्य।